मैसर्स एवरेस्ट होल्डिंग लिमिटेड़

बनाम

श्याम कुमार श्रीवास्तव व अन्य

(मध्यस्थता याचिका संख्या 13 ऑफ 2007)

24 अक्टूबर, 2008

(डॉ. मुकुंदकम शर्मा , जे.)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**,** 1996:

एसएस. 2(एफ), 11(6) और (9) - अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता - मध्यस्थ की नियुक्ति - संयुक्त उद्यम समझौता जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल है - संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन - पार्टियों की सहयोगी कंपनियों द्वारा भुगतान की गई राशि के संबंध में विवाद इक्विटी अंशदान या कामकाजी व्यय के प्रति - उत्तरदाताओं ने दलील दी कि विवाद समझौते के पक्षों के बीच नहीं बल्कि उनकी सहयोगी संस्थाओं के बीच लेनदेन से संबंधित है और इसलिए, मध्यस्थ को कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता है- अभिनिर्धारित किया: एक वैध मध्यस्थता समझौता जेवीए में निहित पार्टियों के बीच है जिसका पार्टियों को पालन करना आवश्यक है- यदि उक्त जेवीए की विषय वस्तु के संबंध में या उससे उत्पन्न समझौते के पार्टियों के बीच कोई विवाद है, तो ऐसे सभी विवाद और मतभेदों पर पारस्परिक रूप से सहमत मध्यस्थ की नियुक्ति करके मध्यस्थता की

प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिया जाना चाहिए - हालांकि जेवीए को समाप्त और रद्द कर दिया गया। हो सकता है, लेकिन यह एक वैध जेवीए था जिसमें उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के लिए एक वैध मध्यस्थता समझौता शामिल था। या जेवीए की विषय वस्तु के संबंध में - जेवीए के निष्पादन और संयुक्त उद्यम कंपनी के कामकाज के लिए पार्टी द्वारा या उसकी ओर से उसके सहयोगियों द्वारा किए गए योगदान के रूप में माना जाएगा और क्या इसे माना जाना चाहिए? विशिष्ट अवधि में पार्टी और जेवीए में खंड भी मध्यस्थ द्वारा तय किए जाने वाले मामले हैं - जेवीए में पार्टियों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि कंपनी के इक्विटी शेयरों को दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा सब्सक्राइब किया जा सकता है या उसके सहयोगियों द्वारा और यह कि उसके सहयोगियों की शेयरधारिता को मान्यता प्राप्त सीमा तक पार्टी की शेयरधारिता के रूप में माना जाना चाहिए। सहयोगियों को भी समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य किया गया था - इसलिए, जो विवाद उत्पन्न होते हैं जेवीए से बाहर, यदि एक मध्यस्थ को भेजा जाता है तो यह किसी भी तरह से कार्यवाही के कारणों का विभाजन या पार्टियों का विभाजन नहीं होगा - पार्टियों के आपसी सहमति होने पर, मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा जो जेवीए से उत्पन्न होने वाले विवाद का फैसला करेगा जितनी जल्दी संभव हो सके। (पैरा 16-19 और 21)

एसबीपी और सीपी. बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य **2005 (4) पूरक एससीआर 688 = (2005) 8 एससीसी 618;** राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी **2006 (4) पूरक। एससीआर 332 = (2006) 7 एससीसी 275 पर भरोसा किया गया।**

सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पंड्या और अन्य 2003 (3) एससीआर 558 = 2003) 5 एससीसी 531 - प्रतिष्ठित।

मध्यस्थता - कंपनी के गठन के लिए इक्विटी योगदान के संबंध में निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ की शक्ति, जो कंपनी के समापन से संबंधित मामला हो सकता है - अभिनिर्धारित : हालांकि मध्यस्थ के पास कंपनी को बंद करने का आदेश देने की कोई शक्ति नहीं होगी क्योंकि ऐसी शक्ति प्रदान की गई है जैसा कि कंपनी अधिनियम के तहत परिकल्पित है, न्यायालय में निहित है, लेकिन मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में, मध्यस्थ हमेशा यह पता लगा सकता है और निर्णय दे सकता है कि कोई कंपनी कार्यात्मक है या नहीं और यदि उस स्थिति में यह कार्यात्मक नहीं थी तो वह हमेशा इसका पता लगा सकता है। वह अपनी परिसंपत्तियों की प्रकृति और स्थिति का पता लगा सकता है और बकाया और देनदारियों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर सकता है और आदेश पारित कर सकता है और उचित उपाय का सहारा भी ले सकता है। (पैरा 17-18)

हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड बनाम स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड **1999 (3) एससीआर 861 = (1999) 5 एससीसी 688 - संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ:

2005 (4) पूरक एससीआर 688	**पर निर्धारित**	**पैरा 13**
2003 (3) एससीआर 558	**विशिष्ट**	**पैरा 15**
2006 (4) पूरक एससीआर 332	**पर भरोसा**	**पैरा 16**
1999 (3) एससीआर 861	**संदर्भित**	**पैरा 18**

मूल नागरिक क्षेत्राधिकार: मध्यस्थता याचिका संख्या 13/2007।

राजीव दत्ता, प्रवीण स्वरूप और एम.एफ. हुमायुनिसा अपीलकर्ता के लिए।

श्याम दिवान, अतुल शंकर माथुर, बॉडी रंगनधन, नुपूर मुखर्जी एवं मैसर्स खेतान एण्ड कम्पनी उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

डॉ. मुकुंदकम शर्मा , जे. 1. यह आदेश याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) और (9) (इसके बाद 'अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रार्थना करने वाली याचिका का निपटारा करेगा। पार्टियों के बीच हुए मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में।

2. याचिकाकर्ता चीन के कानूनों के तहत निगमित एक विदेशी कंपनी है जिसका कार्यालय हांगकांग में है जबकि प्रतिवादी नं. 1 भारत का नागरिक है और प्रतिवादी संख्या का अध्यक्ष है। 2- श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 श्रीवास्तव समूह की कंपनियां हैं और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 तक हैं। 6 और 7 साझेदारी फर्म हैं जो श्रीवास्तव ग्रुप के नाम से कारोबार करती हैं। प्रतिवादी सं. 8, जिसे याचिका में पक्षकार के रूप में भी रखा गया है, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या के बीच संयुक्त उद्यम समझौते (संक्षेप में 'जेवीए') के तहत गठित एक कंपनी है। 1. उक्त कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित और पंजीकृत किया गया था। हालाँकि, उपरोक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 8 का नाम को पार्टियों की श्रृंखला से हटा दिया गया था।

3. दिनांक 08.09.2003 को, एक ओर याचिकाकर्ता और दूसरी ओर प्रतिवादी नंबर 1 के बीच सहयोग प्रदान करने का एक समझौता किया गया था और श्रीवास्तव समूह से संबंधित खदानों से लौह अयस्क के निर्यात के लिए भी समझौता किया गया। उपरोक्त समझौते के अनुसार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच 25.09.2003 को एक जेवीए निष्पादित किया गया था। लौह अयस्क के खनन, प्रसंस्करण और निर्यात के प्रयोजन के लिए 26.03.2004 को पार्टियों के बीच एक और जेवीए निष्पादित किया गया, विशेष रूप से, 25.09.2003 के जेवीए के संबंध में कुछ विवादों को

दूर करने के लिए। उक्त का अनुच्छेद 14.3 जेवीए, जो एक मध्यस्थता खंड है, इस प्रकार हैः

> "यदि पक्ष आपसी समझौते के माध्यम से मामले को हल करने में विफल रहते हैं, तो विवाद को दोनों पक्षों के आपसी समझौते द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। ऐसा मध्यस्थ एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही पूरी की जाएगी और मध्यस्थ की नियुक्ति के तीन महीने के भीतर पुरस्कार दिया जाना चाहिए; इस तरह की मध्यस्थता की लागत दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा की जाएगी। मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके बाद के किसी अधिनियम या संशोधन के प्रावधानों के अनुसार होगी मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।"

4. याचिका में याचिकाकर्ता का रुख यह है कि जेवीए पर हस्ताक्षर करने और जेवीए के तहत एक कंपनी बनाने का पूरा विचार याचिकाकर्ता के विदेशों में लौह अयस्क के व्यापार को बढ़ावा देना और एक मजबूत आपूर्ति आधार सुरक्षित करना था। लौह अयस्क के खनन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उपरोक्त समझौते के निष्पादन के परिणामस्वरूप एवरेस्ट माइनिंग एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड के नाम और

शैली के तहत एक कंपनी बनाई जाएगी। लिमिटेड को 02.06.2004 को निगमित किया गया था। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता कंपनी की सहयोगी कंपनी फोकस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी नंबर 450,000 अमेरिकी डॉलर की राशि अग्रिम की है। 18.02.2004 को पूंजी निवेश की ओर तीसरी कंपनी। इसके बाद 29.07.2004 को, यह कहा गया कि याचिकाकर्ता की एक अन्य सहयोगी कंपनी, एएमजे मार्केटिंग ने प्रतिवादी संख्या 3 को भुगतान किया याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त राशि रु. 51,00,000/- रू. 50,00,000/- और रु. 24,00,000/- कुल रु. 1,25,00,000 निगमित कंपनी, अर्थात् एवरेस्ट माइनिंग एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड के लाभ के लिए ब्याज मुक्त जमा राशि के रूप में - प्रतिवादी संख्या 8।

याचिकाकर्ता का यह भी रुख है कि 20.09.2004 को प्रतिवादी संख्या 3 से जेवीए रद्द करने के लिए अनुचित नोटिस प्राप्त करने पर याचिकाकर्ता हैरान और आश्चर्यचकित था। एफओबीटी मूल्य में कमी के आधार पर जो प्रतिक्रिया प्रतिवादी संख्या 3 के अनुसार जेवीए के लिए एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी थी। उक्त नोटिस में, याचिकाकर्ता को आगे सूचित किया गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उक्त मूल्य में कमी पर विचार करने में संकोच किया था और भारतीय रिजर्व बैंक इण्डिया कभी भी दोनों कंपनियों के बीच जेवीए साबित नहीं करेगा और 06.10.2004 को सही उत्तर दिया गया था, जिसमें उसने प्रतिवादी संख्या 3 की ओर इशारा

किया था कि खेप की कीमत में कमी से न केवल प्रतिवादी संख्या 3 को नुकसान हुआ है फोकस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को भी नुकसान हुआ। इसे आगे प्रतिवादी संख्या 3 की ओर इंगित किया गया कि जेवीए का भविष्य केवल उक्त घटना के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से, जब पार्टियों ने संयुक्त उद्यम को विकसित करने में भारी समय और ऊर्जा का निवेश किया था। उक्त उत्तर द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 से निरस्तीकरण पत्र वापस लेने का अनुरोध किया गया।

04.11.2004 को, याचिकाकर्ता की सहयोगी कंपनी, मैसर्स फोकस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और उसके निदेशक श्री जे.एम. को प्रतिवादी 2 के वकील से एक कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें एम.वी. नामक जहाज के माध्यम से शिपमेंट (लुओ -क्विंग नामक वेसल) में कीमत में कमी के लिए 14 प्रतिशत ब्याज सहित 5,03,319 अमेरिकी डॉलर की राशि की मांग की गई। उपरोक्त नोटिस के उत्तर में बताया कि वे उन मुद्दों को सहयोग करने और हल करने के इच्छुक हैं जो उक्त मुद्दे जेवीए के भीतर हैं। हालाँकि, उत्तरदाताओं का समाधान न होने के कारण मामले का समाधान नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप 15.12.2004 को प्रतिवादी संख्या 1 को एक अनुरोध भेजा गया। यूएस रूपये 7,25,000 की सुरक्षा जमा राशि, यूएस रूपये 11,000 का भुगतान योगदान और प्रतिवादी संख्या 8 के कामकाजी व्यय के लिए 25,00,000/- रुपये का भुगतान किया गया। उपरोक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर 18 प्रतिशत

प्रति वर्ष की ब्याज सहित दर से इस संबंध में एक वकील का नोटिस भी 14.05.2005 को भेजा गया था।

चूंकि कोई राशि वापस नहीं की गई थी, याचिकाकर्ता ने जेवीए में निहित मध्यस्थता खंड का इस्तेमाल किया और दिनांक 16.09.2006 के पत्र के तहत एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध करते हुए इस आशय का एक नोटिस जारी किया गया था। उक्त पत्र में, याचिकाकर्ता ने पीठासीन मध्यस्थ के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.सी. गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया और प्रतिवादी नंबर 1 से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित उक्त नाम से सहमत होने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी सं. 1, हालांकि, अपने वकील के जवाब दिनांक 12.10.2006 के माध्यम से याचिकाकर्ता के दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और इस आधार पर मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से भी इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच जेवीए। अस्तित्व में नहीं है क्योंकि इसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यह कहा गया था कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुए जेवीए के खंड 14.3 का कोई आह्वान नहीं किया जा सकता है।

5. उपरोक्त स्थिति और पार्टियों के रुख को देखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति और जेवीए से उत्पन्न पार्टियों के बीच सभी

विवादों को उक्त मध्यस्थ को संदर्भित करने की प्रार्थना के साथ निर्णय और निर्णय के लिए वर्तमान याचिका दायर की गई थी।

6. नोटिस जारी किया गया और प्राप्त होने पर उत्तरदाता उपस्थित हुए। हालाँकि, याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी नं. 8 को प्रतिवादी संख्या 8 के पते के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। याचिका में उल्लिखित जेवीए कंपनी सही नहीं थी और इसलिए प्रतिवादी 8 का नाम इस न्यायालय के आदेश से दिनांक 28.08.2008 को पक्षकारों की सूची से हटा दिया गया। अन्य सभी उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व उनके वकील के माध्यम से याचिका में किया गया है।

7. मैंने उन पक्षों की ओर से पेश वकील को सुना जिन्होंने रिकॉर्ड पर मौजूद विभिन्न दस्तावेजों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। याचिकाकर्ता के अनुसार एक दीर्घकालिक सहयोग समझौता दिनांक 08.09.2003 को पार्टियों के बीच निष्पादित किया गया था, जिसके अनुसार एक जेवीए में प्रवेश किया गया था और भारत में एक संयुक्त उद्यम कंपनी भी शामिल की गई थी। मेरा ध्यान उक्त जेवीए की ओर आकर्षित हुआ जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है, जिसके अनुसार, पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया और तय किया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि वर्तमान मामले में जेवीए से संबंधित मामलों के संबंध में पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न

हुए हैं, इसलिए, उक्त सभी विवादों को एक मध्यस्थ नियुक्त करके मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाना आवश्यक है।

8. अधिनियम की धारा 11(6) और (9) के तहत दायर याचिका को सावधानीपूर्वक पढ़ने और पक्षों की ओर से पेश वकील को सुनने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से पैसे की वापसी के लिए अपने दावे को सीमित कर रहा है। जेवीए के अनुसरण में और उसके निष्पादन में भुगतान/जमा किया गया और प्रतिवादी संख्या 8 के कामकाजी खर्चों के लिए भुगतान की गई राशि भी प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा जेवीए के लिए भुगतान की गई राशि का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि दिनाक 18.02.2004 को जेवीए के गठन से पहले ही याचिकाकर्ता कंपनी की सहयोगी कंपनी फोकस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने प्रतिवादी संख्या 3 को 450,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी थी कंपनी यानी डेक्कन मिनरल्स प्राइवेट. लिमिटेड पूंजी निवेश की दिशा में उपरोक्त राशि की प्राप्ति वास्तव में अनुच्छेद 4, खंड 4.2 (बी)(आई) के तहत जेवीए में ही दर्ज की गई है। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि किया गया उक्त भुगतान भी जेवीए से संबंधित विवाद का हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी है कि 29.07.2004 को याचिकाकर्ता की एक अन्य सहयोगी कंपनी, एएमजे मार्केटिंग ने प्रतिवादी संख्या 3 को भुगतान किया था। ब्याज मुक्त खाते में 1,25,00,000/- की राशि निम्नलिखित तरीके से

किस्तों में भुगतान करके जमा करें, चेक संख्या 004442 दिनांक 27.07.2004 के माध्यम से 50,00,000/- की राशि जमा करें, चेक नं. 004443 दिनांक 29.07.2004 रुपये 51,00,000 की राशि एवं चेक क्रमांक 048815 दिनांक 16.09.2004 की रू. 24,00,000/- की राशि।

9. हालाँकि, याचिकाकर्ता के उपरोक्त दावे अन्य बातों के साथ.साथ उत्तरदाताओं द्वारा खारिज कर दिए गए हैं कि इनमें से कुछ उपरोक्त दावे जो याचिका में उल्लिखित हैं और पार्टियों के बीच पत्राचार में भी जेवीए से उत्पन्न नहीं होते हैं और वे याचिकाकर्ता की सहयोगी संस्था और उत्तरदाताओं की सहयोगी संस्था के बीच अन्य समझौतों और मामलो के व्यवहार से संबंधित हैं, और इसलिए, उन्हें पार्टियों के बीच जेवीए से उत्पन्न विवादों का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि न तो पार्टियों का विभाजन हो सकता है और न ही मामले का और मौजूदा कानून के तहत ऐसा विभाजन स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए, उपरोक्त याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी के वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त जेवीए हालांकि अस्तित्व में आया और उक्त समझौते के अनुसरण में एक कंपनी, प्रतिवादी संख्या 8 अस्तित्व में आया लेकिन कंपनी में कोई लेन.देन नहीं हुआ और उक्त जेवीए को दिनांक 20.09.2004 से रद्द और समाप्त कर दिया गया। और इसलिए, न तो समझौता अस्तित्व में था और न ही मध्यस्थता खंड, और

इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा उक्त समझौते के खंड 14.3 को लागू करना गलत और अधिकार क्षेत्र के बिना है।

10. पार्टियों की उपरोक्त दलीलों पर मेरा ध्यान गया है और मैंने रिकॉर्ड में रखे गए विभिन्न दस्तावेज़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। जेवीए, जो पार्टियों के बीच विवादों का विषय है, दिनांक 26.03.2004 था और इसे मैसर्स एवरेस्ट होल्डिंग लिमिटेड और श्री श्याम कुमार श्रीवास्तव था। के साथ साथ खनन कंपनियों के बीच दर्ज किया गया जैसा कि अनुच्छेद 1 में दर्शाया गया है, श्रीवास्तव समूह का गठन करते हैं। उक्त जेवीए में "खनन कंपनियां जिन्हें समझौते में संदर्भित किया गया है, वे श्रीवास्तव समूह के स्वामित्व/नियंत्रण वाली निम्नलिखित कंपनियां हैं: (ए) मैसर्स द डेक्कन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (बी) मैसर्स न्यू इंडिया माइनिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (सी) मिनरल्स एंड मेटल्स, (डी) मैसर्स रॉ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट; और (ई) मैसर्स द चैंपियन इंडिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। उपरोक्त जेवीए द्वारा पार्टियों ने अपनी राय व्यक्त की है जल्द से जल्द संभावित तिथि पर उक्त समझौते में उल्लिखित व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य समान इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने और पंजीकृत करने का इरादा व्यक्त है। कंपनी का निगमन "एवरेस्ट माइनिंग एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से हुआ था। जिसे 50,00,000/- रुपए की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ शामिल किया गया था। दोनों पक्ष, अर्थात्, श्रीवास्तव समूह और मैसर्स एवरेस्ट होल्डिंग

लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनी को 10,00,000/- रुपये तक पूंजीकृत करने पर सहमत हुई और प्रत्येक पार्टी को 10/- रुपये के 50,000 इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेने की आवश्यकता थी। उक्त खंड में, अर्थात् खंड 3.3 में, पार्टियां इस बात पर भी सहमत हुईं कि उपरोक्त शेयरों की सदस्यता किसी भी पक्ष द्वारा या उसके सहयोगियों द्वारा ली जा सकती है और सहयोगियों की शेयरधारिता को पार्टी की शेयरधारिता में शामिल किया जाना चाहिए और प्रत्येक पक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे प्रत्येक सहयोगी समझौते के नियमों और शर्तों से बंधे होंगे और उनका अनुपालन करेंगे। इसलिए, उक्त जेवीए में न केवल पार्टियों को मान्यता दी जाती है बल्कि उनके सहयोगियों को भी मान्यता दी जाती है क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि सहयोगी पार्टियां भी पार्टियों की ओर से सदस्यता ले सकें।

11. उक्त जेवीए, जो कि आधे पक्षों का एक स्वीकृत दस्तावेज है, यह भी निर्धारित करता है कि 450,000 यूएस डाॅलर रुपये की राशि श्रीवास्तव ग्रुप के साथ एवरेस्ट होल्डिंग लिमिटेड, द्वारा पहले ही जमा कर दिया गया था जो कि डेक्कन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को टेलीग्राफिक ट्रांसफर द्वारा भुगतान किया गया जो प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व और नियंत्रण वाली खनन कंपनियों में से एक है। और उक्त राशि की प्राप्ति प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी स्वीकार की जाती है।

12. समझौते में एक और खंड है, अर्थात्, 14.2 जो यह निर्धारित करता है कि पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि वे इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित विवाद, विवाद या क्लेम को हल करने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करेंगे, किसी विवाद के अलावा जिसका समाधान उस अनुबंध में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। मैंने पहले ही जेवीए का खंड 14.3 निकाल लिया है, जिसमें कहा गया है कि यदि पार्टियों के बीच कोई विवाद या मतभेद है और वे आपसी समझौते के माध्यम से मामले को हल करने में विफल रहते हैं, तो विवाद को दोनों पक्षों के आपसी समझौते से नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। यह भी कहा गया है कि मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और भाषा अंग्रेजी होगी, जो कि जेवीए का खंड 14.4 है।

13. जब अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका दायर की जाती है। विशेष रूप से, उप-धारा (6) और (8) के तहत, कुछ प्रारंभिक मामलों को मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। एसबीपी और सीपी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य (2005) 8 एससीसी 618 में रिपोर्ट की गई, प्रति बहुमत (6:1) में यह माना गया कि शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 11(6) के तहत भारत का न्याय एक प्रशासनिक शक्ति नहीं है और यह न्यायिक शक्ति है। उक्त निर्णय में यह भी माना गया कि अधिनियम की धारा 11

(6) के तहत कर्तव्य पालन की शक्ति का प्रयोग करते समय, मुख्य न्यायाधीश को यह विचार करना होगा कि क्या उस शक्ति के प्रयोग या प्रदर्शन के लिए धारा द्वारा निर्धारित शर्तें हैं वह कर्तव्य, मौजूद है या नहीं और उसके परिणामस्वरूप मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था यह तय करने के लिए बाध्य है कि क्या उसके पास अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, इस अर्थ में, क्या प्रस्ताव करने वाले पक्षों ने सही उच्च न्यायालय से संपर्क किया है क्या अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में कोई वैध मध्यस्थता समझौता है और क्या उसके सामने अनुरोध करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष है या क्या कोई विवाद मौजूद नहीं था जो मध्यस्थता करने में सक्षम था। उक्त निर्णय में यह भी कहा गया था कि मुख्य न्यायाधीश इस सवाल पर भी फैसला कर सकते हैं कि क्या दावा एक मृत था, या एक लंबे समय से अवरुद्ध दावा था जिसे पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी और क्या पार्टियों ने संतुष्टि दर्ज करके ट्रांस कार्रवाई का निष्कर्ष निकाला है... आपसी अधिकार और दायित्व या आपत्ति के बिना अंतिम भुगतान प्राप्त करके। हालाँकि, न्यायालय ने चेतावनी जारी की कि उस स्तर पर यह तय करना संभव नहीं होगा कि किया गया दावा मध्यस्थता खंड के दायरे में आता है या नहीं और उस प्रश्न को मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना उचित होगा। मध्यस्थता में शामिल दावों के गुण-दोष सहित साक्ष्य लेना। निर्णय में आगे कहा गया है कि इन पहलुओं पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने पर, सी जस्टिस या उनके नामित को यह जांच करनी होगी कि क्या अधिनियम

की धारा 11(6) के तहत उनकी शक्ति के प्रयोग की शर्तें पूरी हुई हैं; और यदि एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना है, जो प्रावधान के संदर्भ में उपयुक्त व्यक्ति है।

14. इसलिए, वर्तमान जांच, जो अधिनियम की धारा 11(6) के प्रावधानों के तहत वर्तमान मामले में मुझे सौंपी गई है, उपरोक्त पहलुओं के इर्द-गिर्द घूमेगी, जो पूर्वोक्त निर्णय में निपटाए गए हैं। उत्तरदाताओं द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया है कि इस न्यायालय के पास याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एक वैध मध्यस्थता समझौता भी है. जेवीए के खंड 14.3 में यह आवश्यक है कि यदि जेवीए से संबंधित मामलों के संबंध में पार्टियों के बीच कोई विवाद है, तो उस पर मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिया जाना आवश्यक है और मध्यस्थ का निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। उपरोक्त खंड मेरे समक्ष न तो विवादित है और न ही प्रश्नांकित है।

15. विवाद उस राशि के संबंध में है जिसका भुगतान याचिकाकर्ता या उसकी सहयोगी कंपनी द्वारा किया जाना बताया गया है। उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उक्त मुद्दे मध्यस्थता समझौते का हिस्सा नहीं हो सकते हैं और ये जेवीए से उत्पन्न होने वाले विवादों का विषय नहीं हैं। उत्तरदाताओं के अनुसार, उक्त विवाद समझौते के पक्षों के बीच नहीं बल्कि अन्य पक्षों, अर्थात् याचिकाकर्ता और उत्तरदाताओं की सहयोगी संस्थाओं के बीच लेनदेन से संबंधित हैं, और इसलिए, वे इससे

उत्पन्न होने वाले विवाद का हिस्सा नहीं बन सकते हैं या जेवीए के संबंध में। उक्त तर्क के समर्थन में उत्तरदाताओं के वकील ने सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पंड्या और अन्य (2003) 5 एससीसी 531 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। उक्त निर्णय में यह माना गया था जब मुकदमे की विषय वस्तु में मध्यस्थता समझौते की विषय वस्तु के साथ-साथ अन्य विवाद भी शामिल हों, तो अधिनियम के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसे मामले को भी मध्यस्थता के लिए भेजा जाना आवश्यक हो। कार्रवाई के कारणों या पक्षों को विभाजित करने और मुकदमे की विषय वस्तु को मध्यस्थों को संदर्भित करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। पार्टी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने, विशेष रूप से, निर्णय के पैराग्राफ 16 पर आधारित किया जो इस प्रकार है:

> "अगला प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह है - भले ही मध्यस्थता, विवाद को आंशिक रूप से संदर्भित करने का कोई प्रावधान नहीं है क्या अधिनियम की धारा 8 के तहत ऐसा पाठ्यक्रम संभव है। हमारे विचार में, धारा 8 की व्याख्या करना मुश्किल होगा जिसके तहत कार्रवाई के कारण का विभाजन, यानी मुकदमे की विषय - वस्तु या कुछ मामलों में उन पक्षों के बीच मुकदमे का विभाजन होता है जो पक्षकार हैं मध्यस्थता समझौता और अन्य संभव है।

यह एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया होगी जिस पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है। यदि किसी मुकदमे की विषय-वस्तु के विभाजन पर विचार किया गया था, तो विधायिका ने ऐसे पाठ्यक्रम की अनुमति देने के लिए उचित भाषा का उपयोग किया होगा। चूंकि भाषा में ऐसा कोई संकेत नहीं है, इसलिए इसका मतलब यह है कि न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्रवाई की विषय वस्तु को विभाजित करने की अनुमति नहीं है।"

उक्त निर्णय के पैराग्राफ 17 में इसे इस प्रकार रखा गया जो निम्नलिखित हैः

"दूसरी बात, मुकदमे को दो भागों में विभाजित करना, एक का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है और दूसरे का निर्णय सिविल कोर्ट द्वारा किया जाना अनिवार्य रूप से कार्यवाही में देरी करेगा। विवाद के शीघ्र निपटान और मुकदमेबाजी की लागत को कम करने का पूरा उद्देश्य होगा ऐसी प्रक्रिया से निराशा होगी। इससे मुकदमेबाजी की लागत और पार्टियों को उत्पीड़न में भी वृद्धि होगी और अवसरों पर दो अलग-अलग मंचों द्वारा विरोधाभासी निर्णय और आदेशों की संभावना भी होती है।

यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा जेवीसी के गठन के लिए इक्विटी योगदान के रूप में भुगतान की गई राशि की वापसी कंपनी के समापन से संबंधित मामला है, और इसलिए, मध्यस्थ के पास कंपनी को बंद करने का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। चूंकि ऐसी शक्ति कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत परिकल्पित के अनुसार अदालत को प्रदान की जाती है और उसमें निहित होती है।

16. सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय, हालांकि, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी में इस न्यायालय के बाद के निर्णय में भिन्न हो गया, जिसकी रिपोर्ट (2006) 7 एससीसी 275 में अंकित किया गए भेद को इंगित करने के लिए, पैराग्राफ 23, 45 और 47 के निर्णय निकालना आवश्यक है जो की निम्नलिखित है:

> "23....एक बार जब उक्त कार्यवाही में निहित पूर्ववर्ती शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो न्यायिक प्राधिकरण वैधानिक रूप से मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य होता है। इसलिए, अन्य बातों के साथ-साथ यह देखना आवश्यक है कि क्या विवाद की विषय-वस्तु मध्यस्थता समझौते के अंतर्गत आती है या नहीं।
>
> 45. सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पंड्या पर विद्वान वकील द्वारा रखा गया भरोसा गलत है।

उसमें, न केवल फर्म के विघटन के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, बल्कि कार्रवाई का एक अलग कारण उत्पन्न हुआ था, जिसमें मध्यस्थता समझौते के पक्षों के अलावा, अन्य पक्षों को भी शामिल किया गया था। उपर्युक्त तथ्य स्थिति में, इस न्यायालय ने कहाः (एससीसी पृष्ठ 535, पैरा 13)

"13. दूसरे, अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब मुकदमे की विषय-वस्तु में मध्यस्थता समझौते के विषय-वस्तु के साथ-साथ अन्य विवाद भी शामिल हों, तो मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना आवश्यक है। ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कारण या पार्टियों को विभाजित करने और मुकदमे की विषय-वस्तु को मध्यस्थों को संदर्भित करने के लिए।"

47. यहां ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यहां पार्टियां मध्यस्थता समझौते की पार्टियां हैं और मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रश्न, यदि कोई हो, तो 1996 अधिनियम की धारा 16 के संदर्भ में मध्यस्थ द्वारा स्वयं निर्धारित किया जा सकता है।"

17. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति के आलोक में, मेरी सुविचारित राय है कि जेवीए में निहित पार्टियों के बीच एक वैध

मध्यस्थता समझौता है, जिसका पार्टियों को पालन करना आवश्यक है और वे उसी से बंधे हैं। अन्य शब्दों में, यदि उक्त समझौते के पक्षकारों के बीच उक्त जेवीए की विषय वस्तु के संबंध में या उससे उत्पन्न कोई विवाद है, तो ऐसे सभी विवादों और मतभेदों पर निर्णय लिया जाना चाहिए और मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिया जाना चाहिए एक पारस्परिक रूप से सहमत मध्यस्थ की नियुक्ति करके। उपरोक्त के अनुसरण में- जेवीए दिनांक 26.03.2004 एवरेस्ट माइनिंग एंड मिनरल प्रा.लि. लिमिटेड को निगमित किया गया था और उक्त कंपनी के निगमन और कामकाज के लिए याचिकाकर्ता द्वारा सहयोगी कंपनियों के माध्यम से विभिन्न राशियाँ भी जमा की गई थीं। पार्टियों के बीच उत्पन्न विवादों के कारण उक्त कंपनी कार्य नहीं कर सकी। ऐसे विवाद जो जेवीए के कामकाज और किए गए विभिन्न जमाओं से संबंधित हैं और जो उक्त जेवीए के संबंध में उत्पन्न हुए हैं, उन पर जेवीए के खंड 14.3 के तहत परिकल्पित मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से विचार और निर्णय लिया जाना आवश्यक है। यद्यपि जेवीए को समाप्त कर दिया गया है और जैसा कि कहा गया है, रद्द कर दिया गया है, लेकिन यह एक वैध जेवीए था जिसमें जेवीए की विषय वस्तु के संबंध में या उससे उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए एक वैध मध्यस्थता समझौता था। प्रतिवादी का यह तर्क कि विवादों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि समझौता आज तक अस्तित्व में नहीं है, इसलिए योग्यता से रहित है।

18. यह सच है कि मध्यस्थ के पास कंपनी को बंद करने का आदेश देने की कोई शक्ति नहीं होगी क्योंकि ऐसी शक्ति एक अदालत को दी गई है और उसमें निहित है जैसा कि हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड बनाम स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड [(1999) 5 एससीसी 688]। इस अदालत के फैसले के मद्देनजर कंपनी अधिनियम के तहत परिकल्पित किया गया है। लेकिन मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में, मध्यस्थ हमेशा यह पता लगा सकता है और निर्णय दे सकता है कि कोई कंपनी कार्यात्मक है या नहीं और यदि उस स्थिति में यह कार्यात्मक नहीं थी तो वह हमेशा इसकी संपत्ति की प्रकृति और स्थिति का पता लगा सकता है और कर सकता है। बकाया और देनदारियों के संबंध में निर्देश जारी करें और आदेश पारित करें और उचित उपाय का सहारा लें।

19. ऐसे सभी विवाद चाहे याचिकाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से जमा की गई सुरक्षा जमा के भुगतान से संबंधित हों और इक्विटी योगदान या कामकाजी खर्चों के लिए किए गए योगदान से संबंधित हों, यदि कोई हो, तो वापस किया जाना चाहिए या नहीं और यदि लौटाया जाना चाहिए तो कितनी राशि होनी चाहिए लौटाए जाने पर जेवीए में पार्टियों द्वारा सहमति के अनुसार मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा जेवीए के निष्पादन और संयुक्त उद्यम समिति के कामकाज के लिए किया गया योगदान-पार्टी द्वारा या उसकी ओर से उसके सहयोगियों द्वारा दिया गया पैसा, को जेवीए में विशिष्ट अवधि और खंड में पार्टी द्वारा किए गए

योगदान के रूप में माना जाना चाहिए, यह भी मध्यस्थ द्वारा तय किए जाने वाले मामले हैं। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जेवीए में पार्टियों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि कंपनी के इक्विटी शेयरों को पार्टियों या उसके सहयोगियों में से किसी एक द्वारा सब्सक्राइब किया जा सकता है और इसके सहयोगियों की शेयरधारिता को माना जाना चाहिए। पार्टी की शेयरधारिता को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। सहयोगियों को भी समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य किया गया था। इसलिए, मेरी सुविचारित राय में, जेवीए से उत्पन्न होने वाले विवादों को यदि मध्यस्थ के पास भेजा जाता है, तो यह किसी भी तरह से कार्रवाई के कारणों के विभाजन या पार्टियों के विभाजन की राशि नहीं होगी।

20. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की सहयोगी संस्थाओं के बीच अलग-अलग और स्वतंत्र समझौतों से उत्पन्न होने वाले अन्य विवाद भी हो सकते हैं। ऐसे विवादों का निर्णय कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे सभी विवाद जिनकी यहां पहले पहचान की गई है और उल्लेख किया गया है और जो जेवीए के संबंध में और उससे उत्पन्न होते हैं, उन्हें मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में एक मध्यस्थ नियुक्त करके तय किया जाना चाहिए।

21. बहस के दौरान पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि यदि न्यायालय विवादों को मध्यस्थ के पास भेजने का निर्णय लेता है तो उस स्थिति में

इसे न्यायमूर्ति वी.एन. खरे, के पास भेजा जा सकता है। इस न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए दोनों पक्ष आपसी सहमति से उन्हें मध्यस्थ बनाने पर सहमत हुए। उक्त समझौते के परिणामस्वरूप, मैं न्यायमूर्ति वी.एन. खरे को नियुक्त करता हूं। इस न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश खरे को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया और उनसे जेवीए से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच विवादों को यथासंभव शीघ्रता से निपटाने का अनुरोध किया गया। विद्वान मध्यस्थ के लिए पार्टियों के साथ चर्चा के बाद अपना पारिश्रमिक तय करने का अधिकार खुला रहेगा।

22. तदनुसार, याचिका का निपटारा किया जाता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यहां की गई टिप्पणियाँ केवल इस मुद्दे को तय करने के उद्देश्य से हैं कि विवाद हैं या नहीं मध्यस्थ के पास भेजा जाना चाहिए आवश्यक रूप से यहां किए गए किसी भी अवलोकन को दावों की योग्यता पर व्यक्त कोई विचार या राय नहीं माना जाएगा।

मध्यस्थता याचिका निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी धर्मराज मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।